WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

APRIL 2024

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax: 0121-4346686**

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Prashant Kumar

INDEX

- बिजली चोरी की पोल खोलेगी एमआरआई
- अब मीटर रीडर ही सही करेगा आरडीएफ बिजली बिल, व्यवस्था तत्काल लागू की
- ऑफलाइन आईटीआर भरने के लिए फार्म जारी
- आईटीआर फॉर्म एक, दो और चार ई- फाइलिंग पोर्टल पर जारी
- आयकर व्यवस्था में नया बदलाव नहीं
- एमएसएमई उद्योग को 45 दिन में मिलेगा भुगतान
- अब बैंको में नहीं लगेगी कतार यूपीआई से जमा होगी नकदी
- बंधक संपत्ति पर पांच लाख से अधिक नहीं देना होगा शुल्क
- 'We are ending toll': Nitin Gadkari on new toll system
- DGFT notifies policy for general authorisation for export of certain goods under SCOMET category
- Centre to fast-track enrolment of unorganised workers on e-Shram
- RBI's professional management helped in dealing with external uncertainties: FM Sitharaman
- Niti Aayog bats for easy financing, e-commerce push to boost MSME exports
- Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

बिजली चोरी की पोल खोलेगी एमआरआई

अब कम किलोवाट पर अधिक लोड चलाने वाले और मीटर शंट करके बिजली चोरी वाले विभाग से बच नहीं सकेंगे। पीवीवीएनएल की ओर से अब तीन और चार किलोवाट के बिजली कनेक्शनों की भी एमआरआई (मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट) कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए है।

बिजली चोरी और बिजली की खपत का पता लगाने के लिए पावर कारपोरेशन की ओर से 5 से 9 किलोवाट के विघुत कनेक्शन की एमआरआई कराई जा रही थी। इसके वांछित परिणाम आने के बाद अब विभाग ने तीन और चार किलोवाट के कनेक्शन की एमआरआई कराने का निर्णय लिया है।

मार्च से ऐसे विघुत कनेक्शनों की एमआरआई शुरू हो जाएगी। विघुत विभाग के कर्मचारी घर - घर जाकर उपभोक्ताओं के मीटर की जांच करेंगे।

अब मार्च से 3 और 4 केवी के विघुत कनेक्शन की भी एमआरआई कराई जाएगी। इस संबंध में आदेश प्राप्त हो गए हैं। संबंधित कंपनी को भी कर्मचारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com

A Pioneer Unit for Manufacturing of:

"MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD"

एमआरआई का मतलब मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट

एमआरआई का मतलब मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट से है। इस उपकरण के इस्तेमाल से मीटरो की जांच की जा रही हैं। मीटर में इंस्ट्रूमेंट को लगाकर पता लगाया जा रहा हैं कि जहां कनेक्शन लगा हैं, वहां बिजली की खपत कितनी हैं और बिजली खर्च कितनी हो रही हैं। अगर बिजली डिमांड से अधिक फूंकी जा रही हैं तो इसका तुरंत पता चल जाएगा। मीटर पर अधिक लोड हैं तो वह भी सामने आ जाएगा। फिर लोड के आधार पर मीटर की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर मीटर को टैंपर करके बिजली चोरी की जा रही हैं तो इसका भी पता चल जाएगा।

अब मीटर रीडर ही सही करेगा आरडीएफ बिजली बिल, व्यवस्था तत्काल लागू की एक्सईएन से लेकर उपकेंद्र के जेई के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे

बिजली उपभोक्ताओं को आरडीएफ (रीडिंग डिफेक्टिव फंक्शन) बिल मीटर रीडिंग के मुताबिक संशोधित कराने के लिए वितरण खंड के एक्सईएन से लेकर उपकेंद्र के जेई के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब वही मीटर रीडर बिल सही करेगा, जिसने मीटर को आरडीएफ दर्शाकर बिल बनाया होगा।

मीटर रीडर यह का उपभोक्ता के घर पर करेगा। एक माह का जो आरडीएफ बिल लगभग 800 रूपए का बना होगा, वह सिस्टम से अपने आप ख़तम होकर रीडिंग के हिसाब से रकम का बन जाएगा। इसके लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है। इस बदलाव से ही मीटर रीडर को आरडीएफ बिल को सही करने की सहूलियत मिली है। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने बिलिंग सॉफ्टवेयर में किए गए बदलाव का सर्कुलर जारी कर यह सुविधा तत्काल प्रभाव से प्रदेश भर में लागू कर दी गई है।

इस तरह संशोदित होगा बिल

उपभोक्ता के मीटर में 100 यूनिट रीडिंग है, लेकिन, मीटर रीडर में उपभोक्ता की चौखट पर गए बिना ही या रीडिंग पढ़ने के बाद भी सिस्टम में 50 यूनिट फीड कर बिल बना दिया। सॉफ्टवेयर जैसे ही 50 यूनिट का बिल बनाएगा तोह आरडीएफ हो जाएगा। वजह यह की 50 यूनिट रीडिंग पहले ही सिस्टम में फीड हो चुकी हैं, जिसे दुबारा स्वीकार नहीं करेगा। फिर उपभोक्ता को बिल संशोधित कराने के लिए कार्यालय में भटकना पड़ता था। अब नई व्यवस्था में जिस रीडर ने फरवरी में मीटर की 100 यूनिट की जगह 50 यूनिट फीड कर आरडीएफ बिल बनाया था, वही मार्च में मीटर की सही रीडिंग फीड करेगा तो ऑटोमेटिक बिल संशोधित होकर बन जाएगा। यानी जितनी यूनिट के बिल की देनदारी होगी उतनी हिओ रकम का बिल बनेगा।

ऑफलाइन आईटीआर भरने के लिए फार्म जारी

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023 -24 (आकलन वर्ष 2024 -25) के लिए लागू आईटीआर -1 और आईटीआर -4 के लिए ऑफलाइन फॉर्म (जेसन सुविधा) जारी कर दिए हैं। इनका उपयोग 1 अप्रैल से आईटीआर दाखिल करने के लिए किया जाएगा। जेसन (JSON) सुविधा का इस्तेमाल पहले से भरे हुए विवरण को ऑफलाइन प्रारूप में डाउनलोड या इंपोर्ट करते समय किया जाता हैं।

आयकर विभाग आईटीआर को ऑनलाइन या आंशिक ऑफलाइन मोड के जरिए दाखिल करने की अनुमति देता हैं। ऑफलाइन तरीके से आईटीआर भरते समय जरुरी लेनदेन, कर ब्योरा'और अन्य जानकारियां पहले से ही भरी होती हैं। विभाग ये विवरण फॉर्म -16 और फॉर्म -26 एएस से लेता हैं और आईटीआर में स्वचालित तरीके से दर्ज कर देता हैं। करदाता को केवल उन्हें सत्यापित करना होता हैं।

कितने तरह के आईटीआर फॉर्म

- **आईटीआर -1 (सहज) :** यह उन लोगो के लिए है , जिनकी कुल 50 लाख रुपये तक है। इसमें वेतन से आय , घर की संपत्ति , ब्याज से अर्जित आय शामिल होती है।
- **आईटीआर -4 (सुगम)** : यह उनके लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें व्यवसाय और पेशे से आय शामिल है।
- **आईटीआर -2 और 3 :** इसका इस्तेमाल आवसीय संपत्ति से आय अर्जित करने वाले लोग कर सकते है जबकि आईटीआर -3 फॉर्म कारोबार एवं पेशे से लाभ अर्जित करने वाले लोगों के लिए है।

क्या है जेसन सुविधा

जेसन सुविधा का इस्तेमाल कर फॉर्म को ऑफलाइन तरीके से भरा जाता है। इसके लिए जेसन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। करदाता को वित्त वर्ष के लिए लागू आय और अन्य विवरण खुद से भरने होंगे। ये सुविधा खासकर उन करदाताओं के लिए है, जिनके आयकर और लेनदेन विवरण अधिक होते हैं। एक बार सभी जानकारी भरने के बाद इसे ई - फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 27432

यहां से डाउनलोड करें

जेसन फॉर्म को आयकर विभाग के पोर्टल से डाउनलोड किया जाता है। यहां 'आयकर रिटर्न दाखिल करें ' विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां जेसन यूटिलिटी का लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर डाउनलोड किया जा सकता है।

ऑनलाइन फॉर्म जारी नहीं: विभाग ने अभी तक वित्त वर्ष 2023 -24 के लिए ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जारी नहीं किए हैं, केवल इन्हें अधिसूचित किया गया है।

आईटीआर फॉर्म एक, दो और चार ई- फाइलिंग पोर्टल पर जारी

पिछले वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भर सकते हैं करदाता 31 जुलाई है अंतिम तिथि

आयकर विभाग ने पिछले वित्त वर्ष यानी 2023 -24 के लिए आईटीआर(आयकर रिटर्न) फॉर्म एक, दो और चार को एक अप्रैल, 2024 से ई - फाइलिंग पोर्टल पर जारी कर दिया है। आयकरदाता अपनी आय के अनुसार 2023 -24 का रिटर्न भरने के लिए इन फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।

फॉर्म -1: वे आयकरदाता इसे भर सकते है, जो नौकरीपेशा हैं। साथ ही, अन्य साधनों से जैसे ब्याज, लाभांश और पेंशन के साथ कृषि से 50 हजार रुपये तक आय हो। हालांकि, कुल सालाना आय 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

फॉर्म -2: वैसे आयकरदाता जिनके पास एक से ज्यादा मकान हैं और जिन्हें कैपिटल गेन का लाभ मिल रहा है, वे इसे भर सकते हैं।

फॉर्म -3: यह फॉर्म उनके लिए है, जिनकी आय कारोबार से होती है और जो पेशेवर 44एडी , 44एडीए और 44एई के दायरे में आते हैं।

आयकर व्यवस्था में नया बदलाव नहीं

वित्त मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024 -25 में लोगों के लिए नई आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है। व्यक्तिगत करदाता अपना आईटीआर दाखिल करते समय इस व्यवस्था से बहार निकलने का विकल्प चुन सकते हैं।

मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर जारी उन सूचनाओं के बाद दिया जिसमें एक अप्रैल से प्रभावी नई कर व्यवस्था में कुछ बदलावों का दवा किया गया है। मंत्रालय ने कहा, एक अप्रैल 2024 से कोई नया बदलाव नहीं किया गया है।

एक अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष में लोगों के लिए संशोधित नई आयकर व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत कर दरें हयकाफ़ी कमहं हैं। हालांकि, उसमें पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट तथा कटौती (वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा) का लाभ मौजूद नहीं है।

मंत्रालय ने कहा, नई कर व्यवस्था ' डिफ़ॉल्ट ' कर व्यवस्था है। हालांकि करदाता उस कर व्यवस्था (पुरानी या नई) को चुन सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए फायदेमंद है। नई कर व्यवस्था से बहार निकलने का विकल्प वर्ष 2024 -25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है।

- नई कर व्यवस्था से निकल सकते हैं करदाता
- सोशल मीडिया पर आईं थी बदलाव की खबर

STAG INTERNATIONAL

Manufacturers & Exporters of:
Sports Goods
A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103
Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035
Fax: 0121-2441009
Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

एमएसएमई उद्योग को 45 दिन में मिलेगा भुगतान

विफल रहने पर कारोबारियों को खर्च के बजाय देना होगा कर

सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले यानी एमएसएमई उद्योगों को एक अप्रैल से किसी भी कारोबार का 45 दिन में पैसा मिल जाया करेगा। अगर कोई कारोबारी 45 दिन में भुगतान नहीं करता है तो उसके खाताबही में इस देनदारी को आय मान लिया जाएगा और इस पर उसे टैक्स देना होगा। हालांकि, अगर वह इसका देरी से भुगतान करता है तो उसे अगले वित्त वर्ष में टैक्स के सामने इस रकम को समायोजित किया जा सकता है।

दरअसल, नए नियमों के तहत सेक्शन 43 बी (एच) को चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 से लागू किया गया है इसके तहत अगर एमएसएमई और कारोबारी के बीच करार हुआ है तो इस आधार पर एमएसएमई को 45 दिन में पैसा मिलना चाहिए। एमएसएमई के लिए तो वैसे यह नियम अच्छा है, पर उनको डर भी है कि इससे बड़े खरीदार उनसे सौदा तोड़ सकते हैं। वे किसी और साधन से खरीद सकते हैं। नियमों के मुताबिक, वो एमएसएमई जो सरकार के उद्यम में पंजीकृत नहीं हैं या ऐसे कारोबार जो एमएसएमई में नहीं आते हैं, कारोबारी ऐसे लोगों से खरीद बढ़ा देंगे। क्योंकि यहां पर 45 दिन का नियम लागू नहीं है।

वहीं, यूपी कपड़ा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष अशोक मोतियानी का कहना है कि नए नियम को कारोबारी समझ नहीं पाए हैं। खुदरा कारोबार पहले से प्रभावित हैं। इस नियम को एक साल के लिए बढ़ाने की मांग वित्तमंत्री से की गई थी।

30 फीसदी का आयकर लगेगा

कोई व्यापारी 45 दिन में भुगतान नहीं करता है तो भुगतान वाली रकम को कमाई मान कर 30% आयकर लगेगा। इस रकम का अगले वित्त वर्ष में भुगतान किया जाता है तो फिर उस साल में कुल आयकर की देनदारी में इसे समाहित किया जाएगा। इसमें भी पेंच यह है कि अगर किसी व्यापारी ने 10 लाख का माल खरीदा। अगर 7 लाख चुका दिया और 3 लाख बाकी रह गया। अगले साल अगर उसका कारोबार दो ही लाख का होता है तो फिर तीन लाख रुपये में से एक लाख रुपये उसके अगले साल समाहित करना होगा।

अब बैंको में नहीं लगेगी कतार यूपीआई से जमा होगी नकदी
आरबीआई ग्राहकों के लिए शुरू करेगा सुविधा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंक खाते में नकदी जमा करने की बड़ी सुविधा देने जा रहा है। कतार में लगे बिना नकदी जमा करने वाली मशीन (सीडीएम) में यूपीआई के जरिये भी रकम जमा की जा सकेगी।

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, बैंकों की शाखाओं में सीडीएम लगाई जाएंगी। इससे शाखाओं पर भार कम होगा। इसके अलावा, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआई कार्डधारकों को बैंक खाताधारकों की तरह तीसरे पक्ष के यूपीआई से भुगतान की सुविधा देने की भी तैयारी की जा रही है। अभी पीपीआई से यूपीआई भुगतान सिर्फ पीपीआई कार्ड जारी करने वाले की ओर से उपलब्ध कराई गई वेबसाइट या मोबाइल एप के जरिये ही किया जा सकता है। इससे पीपीआई कार्डधारकों को बैंक खाताधारकों की तरह यूपीआई भुगतान करने में मदद मिलेगी। छोटी राशि के लेनदेन में डिजिटल माध्यम को बढ़ावा मिलेगा। आरबीआई इन उपायों के बारे में जल्द ही दिशा - निर्देश जारी करेगा।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals, Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

बंधक संपत्ति पर पांच लाख से अधिक नहीं देना होगा शुल्क

बंधक प्लाट और संपत्ति के मामले में स्टांप ड्यूटी और विकास शुल्क को लेकर वर्षो से चली आ रही गलतफहमी को साशन ने दूर कर दिया हैं। साशनादेश से स्पष्ट किया गया हैं कि संपत्ति कितनी भी महंगी हो, उससे स्टांप ड्यूटी व विकास शुल्क मिलकर अधिकतम धनराशि पांच लाख रुपये ही ली जा सकती हैं।

साशन ने 2001 में अधिसुचना जारी की थी की बंधक संपत्ति के मामले में स्टांप ड्यूटी को मिलकर अधिकतम धनराशि पांच लाख रुपये तक लगेगी। इसके बाद 2008 में छूट दे दी कि 0.5 प्रतिशत ही स्टांप ड्यूटी लगेगी। साथ ही नगर निकाय की सीमा में होने पर दो प्रतिशत विकास शुल्क भी इसी के साथ जोड़ा जाता हैं। समय -समय पर आए शासनादेश से निबंधक कार्यालय के स्तर पर भरम की स्थिति होने लगी। इसके चलते दो प्रतिशत विकास शुल्क़ और 0.5 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी के आधार पर संपत्ति का आकलन किया जाने लगा। ऐसे में यदि किसी की संपत्ति तीन करोड़ रुपये की है तो उससे विकास शुल्क व स्टांप ड्यूटी को मिलकर 7.50 लाख रुपये लिया जाने लगा। इस तरह से पांच लाख रुपये से अधिक लिए जाने पर बड़ी संख्या में लोगो ने मुकदमा दायर किया और कुछ ने आपत्ति करते हुए अपील दाखिल की। शिकायतें मिलने पर शासन ने विभिन्न स्तरों पर बैठक करके अब प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन ने इस बाबत स्पष्टीकरण जारी किया हैं। डीआईजी स्टांप लखनऊ ने इस साशनादेश की पुष्टि की है। ऐसे में अब इससे संबंधित सभी मुकदमे निस्तारित हो जाएंगे।

- 0.5 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगेगी
- 2 प्रतिशत विकास शुल्क लगेगा
- 5 लाख अधिकतम दोनों शुल्क मिलाकर देना होगा
- बैंक से ऋण लेने वालों और बिल्डरों को मिली बड़ी राहत
- शासन का स्पष्टीकरण, पुराने मुकदमे, अपील होंगी निस्तारित

We are ending toll': Nitin Gadkari on new toll system

The Union Transport Minister Nitin Gadkari today said that the government is ending toll and the new satellite based toll collection system will be introduced soon. "Now we are ending toll and there will be a satellite base toll collection system. Money will be deducted from your bank account and the amount of road you cover will be charged accordingly. Through this time and money can be saved. Earlier, it used to take 9 hours to travel from Mumbai to Pune, now it is reduced to 2 hours," Nitin Gadkari told

Discussing the Bharatmala Pariyojana, which aims to develop approximately 26,000 km of economic corridors, Nitin Gadkari emphasized their significance alongside the Golden Quadrilateral (GQ) and North-South and East-West (NS-EW) corridors in handling the bulk of freight traffic on roads. He expressed confidence that the project will revolutionize the nation's future by 2024. Gadkari articulated his ambition to elevate India's National Highway road network to the standard of America, expressing assurance in his ability to achieve this goal.
Earlier in December, Nitin Gadkari had announced that the National Highways Authority of India (NHAI) aims to roll out this new system by March 2024. Efforts to streamline processes and reduce waiting times at toll plazas have been communicated to the World Bank. With the introduction of FASTag, the average waiting time at toll plazas has significantly decreased to just 47 seconds, marking a notable improvement from the previous average of 714 seconds.

Construction and expansion activities on National Highways have seen a rise of approximately 10 per cent between April and November of the current fiscal year compared to the same period from 2011 to 2023. However, the allocation of new construction projects has witnessed a decline of 52 per cent this year.

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

DGFT notifies policy for general authorisation for export of certain goods under SCOMET category

New Delhi, The commerce ministry on Wednesday notified a policy for general authorisation for the export of certain telecommunication-related and information security-related items under a SCOMET category to grant one-time bulk licences. A detailed procedure for these authorisations has also been notified by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT).

Special chemicals, organisms, materials, equipment and technologies (SCOMET) items are dual-use goods.

"The policy for general authorisation for export of telecommunication-related items under SCOMET category...and export of information security items under SCOMET category...to grant one-time bulk licences for these items has been notified," the DGFT said in a notification.

The applicant exporter will have to submit an application for getting a one-time license through the online SCOMET portal and attach the information in the prescribed format.

Centre to fast-track enrolment of unorganised workers on e-Shram

The Centre is looking to fast track onboarding of unorganised sector workers on e-Shram portal, which provides a universal account number (UAN) to unorganised sector workers and supports them with skilling and employment initiatives.

The labour and employment ministry has initiated discussions with other central ministries dealing with weavers, handloom workers, fishermen and fisherwomen, toddy tappers, leather workers, plantation labourers and beedi workers, and state governments, and has called a meeting with all stakeholders on April 4, a senior government official told ET.
"The idea is to integrate all the scattered data on the Aadhaar-authenticated e-Shram

portal, do away with duplication of data and firm up the data so that India has an exact number of unorganised workers, verified by Aadhar," the official said.

The move comes ahead of the Lok Sabha elections to be held from April 19 to June 1. It is anticipated that the new government, which will be formed in June, could unveil some form of social security benefits for unorganised sector workers or roll out the long-pending Labour Codes, and data from the portal will come handy.

Since 2023, the labour ministry has been linking data from different schemes with e-Shram data to identify e-Shram registrants who have not yet received the benefits of these schemes.

The portal, launched in August 2021, has 295 million unorganised workers as on date with average daily enrolment of 20,000 workers. The government had estimated the country's unorganised workforce at 370 million at the time of the launch of the portal. Agricultural workers constitute more than 50% of the total registrations at 154.2 million, followed by domestic workers (28.4 million), construction workers (26.5 million), and workers in the apparel sector (18.7 million). The data captured on the portal include name, occupation, address, educational qualification, skill types and family details of every unorganised worker registered on the portal, helping the government to track the impact of the existing central and state social sector schemes on them.

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

RBI's professional management helped in dealing with external uncertainties: FM Sitharaman

Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday said the professional management of the Reserve Bank of India (RBI) significantly improved India's capacity to take care of external imbalances and uncertainties. Speaking at the occasion of 90th anniversary of the RBI, the finance minister lauded the central bank for its role in improving the balance sheet problems faced by banks.
"Managing India's banks is something which I recall at this time," she said, adding that a decade ago India had a "balance sheet problem", while today there is a "balance sheet advantage" because of the collaborative effort of the government and the RBI.

The asset quality management, prompt corrective action framework are all great functions well carried out by "our true regulator of the banks Reserve Bank of India", she said.

Sitharaman further said inflation management, despite monetary tightening pressures, has stablised government bond (G-secs) yields which is important for the economy.

Niti Aayog bats for easy financing, e-commerce push to boost MSME exports

Niti Aayog has called for easing of access to export finance and a concerted push to boost e-commerce exports to realise the potential of the country's micro, small, and medium enterprises (MSMEs).
The Aayog said small firms have encountered difficulties in tapping into export markets due to the inherent obstacles posed by economies of scale. "It proves more challenging for small enterprises to enter foreign markets, adhere to compliance requirements, achieve cost-effective production, and efficiently manage logistics for clients," it added.
"By modifying our business environment to facilitate seamless exports through e-commerce platforms, coupled with addressing essential ease-of-doing-business factors, we have the potential to catalyse a radical transformation of our MSME sector into a formidable growth engine," the report said.
As part of six key recommendations, Niti Aayog called for "green channel" clearances of MSME e-commerce exporters. It said that India has not been able to tap into e-commerce to work around market access barriers, unlike China. In 2022, China's e-commerce exports by MSMEs were worth $200 billion, which is 100 times that of exports by Indian MSMEs.
"One key reason for this gap is the cumbersome compliance process associated with

exports, especially when it comes to payment reconciliation, which is particularly challenging for a new or small exporter. To boost e-commerce exports, it is essential to create distinction between Exporter on Record (EOR) and Seller on Record (SOR), allow reduction in invoice value without any percentage ceiling for all e-commerce exports, introduce annual financial reconciliation process for e-commerce exporters, exempt import duties on rejects/returns, consider an exemption on reconciliation requirements for shipments up to $1000 until NTN (National Trade Network) is implemented and creating a green channel clearance for e-commerce exports," the report said.

The report jointly prepared by Niti Aayog and the non-profit Foundation for Economic Development, said that India needs a NTN to ease compliance burdens for MSMEs. This trade network would operate as an end-to-end single window system.

"The Ministry of Commerce could form a task force to review the status of previous initiatives in this regard and create a time-bound program to implement a national trade network on par with the best in the world," the report said.

Access to finance is regularly seen as a key bottleneck for MSMEs. Towards this end, promotion of Export Credit Guarantee can help improve working capital availability for MSMEs, according to the Aayog.

"The current uptake of ECGC (Export Credit Guarantee Corporation) schemes is only 10 per cent and the government must create an incentive package to increase it to 50 per cent or more. Finally, a single marketplace can be created, like in the case of higher education loans, where all providers of export credit can compete for business and help reduce the cost to MSMEs," the report said.

The report also said that a single information portal must be put in place to address the asymmetry of information available to MSME exporters with the help of artificial intelligence, which could provide accurate data to vendors on tariffs, compliance, finance, and availability of incentives.

Data also needs to be assessed accurately, according to the report. "The existing estimates of MSME exports are likely unreliable and almost certainly inflated, given that they rely on an outdated list of reserved sectors for MSMEs. Initiating any improvement requires accurate measurement and consistent tracking of impact."

The central think tank has also called for exemption of MSMEs from compliance burdens for a determined period; any errors in compliance must be forgiven as MSMEs learn the ropes of export markets.

"On the other hand, a process must be created for time-bound disbursement of incentives so that working capital is not blocked for MSMEs," it said

According to a statement issued along with the report, the steps can lead to a fifteen-fold increase in India's MSME exports to $30 billion in the coming years. Data used in the report said that there is an export potential of $318 billion for MSMEs to tap into in segments like herbal supplements and Ayurveda products, wood products, jewellery, handicrafts, and handloom textiles.

Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

Nipro PharmaPackaging India is part of Nipro Corporation Japan. Nipro, a global healthcare company employs over 35k colleagues and has a culture of high performance, customer focus, and employee engagement. This has led Nipro PharmaPackaging India to being awarded with the certificate of the Great Place to Work – Oct' 22 – Oct'23. In addition to the above achievement, Nipro PharmaPackaging India has now earned its recognition as being one of the top 50 "India's Best Workplaces in Manufacturing 2023".

Ashish Moghe, the Managing Director of Nipro in India, states, "Nipro's dedication to investing in its workforce is a key factor in its success. In 2022, Nipro PharmaPackaging India gathered further pace in the last year and crossed a few milestones. One such milestone was getting certified as a Great Place To Work! The Great Place to Work® Certification Program is the first step for an organization on its journey of building a High-Trust, High-Performance Culture™ and our organization has successfully accomplished this milestone.

To continue the same path of progress and development for us as individuals and as an organization we also enrolled ourselves for assessment for yet another prestigious certification, which is TOP 50India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. This year, 201 organizations in the Manufacturing sector undertook this assessment. All these organizations underwent a rigorous assessment. The results are finally out, and it gives me an immense amount of joy and pride to share that both plants of Nipro PharmaPackaging India (Meerut & Pune) HAVE WON THIS CERTIFICATION!!

I feel honoured to be a part of such a fantastic team. Looking forward to creating many more milestones"

"We are thrilled to receive the recognition as India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. We are committed to fostering an environment of transparency, teamwork, and participation. Our organization promotes bonding among colleagues and encourages continuous improvement.Our team takes pride in working for a Great Place to Work certified company, and this recognition not only attracts top talent but also builds loyalty among our employees. The Trust Index study conducted by Great Place to Work provides valuable insights for us to improve as an organization. We strive to be an employer of choice and this recognition is a testament to our efforts.", states Mr. Juned Akhtar(General Manager- Human Resource, Nipro PharmaPackaging India Pvt. Ltd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX